



एस.के. हालदार  
अध्यक्ष

## सन्देश

दिनांक 07 फरवरी, 2021 को सुबह में उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी, जो अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक भूस्खलन हुआ, जिससे ऋषिगंगा नदी में अचानक जलस्तर में वृद्धि हुई। इससे डाउनस्ट्रीम में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को भारी क्षति हुई और जान-माल के नुकसान की सूचना भी मिली। धौलीगंगा नदी के संगम के डाउनस्ट्रीम में अलकनंदा पर जोशीमठ पर केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निगरानी स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी जिसमें पूर्व में दर्ज किए गए एचएफएल से 3 मी. अधिक जलस्तर देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलकनंदा और

हरिद्वार तक गंगा बेसिन में तैनात केंद्रीय जल आयोग के सभी कर्मचारी को हाई एलर्ट पर रखा गया तथा लगातार जलस्तर की निगरानी का आदेश दिया गया।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ की स्थिति का तुरंत आकलन किया गया और यह सूचना दी गई कि जोशीमठ के बाद डाउनस्ट्रीम में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और जलस्तर में वृद्धि में बहुत हद तक नियंत्रण हो चुका है। उसी दिन, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को निदेश दिया गया कि वे आपस में नजदीकी तालमेल के साथ कार्य करते हुए राज्य प्रशासन को सभी वांछित सहायता करें। मैंने अन्य मंत्रालयों तथा सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उस बैठक में भाग लिया।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) तथा इससे संबंधित खतरे सरकारी एजेंसियों की कार्यसूची में है; हालांकि इस घटना ने सरकारी एजेंसियों को भविष्य में

ऐसी स्थिति को प्रभावी रूप से संभालने हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना तैयार करने हेतु चेताया है।

इस माह के दौरान एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द इंडियन नेशनल कमिटी ऑन लार्ज डैम्स (आईएनसीओएलडी), नई दिल्ली ने केंद्रीय जल आयोग और ड्रिप के सहयोग से आईसीओएलडी के तत्वाधान में "सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस बैठक का उद्घाटन जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मुख्य अतिथि थे के द्वारा किया गया और श्री आर.के. सिंह, ऊर्जा एवं नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय जल आयोग ने इसके आयोजन में प्रमुख रूप से योगदान किया जिसने इस विषय पर जानकारी साझा करने और नीति आदान के लिए एक उत्तम मंच उपलब्ध कराया।

गौतम कांत

## दवाई भी, कड़ाई भी

कोविड- 19 का टीका लगवाने के लिए आज ही [www.cowin.gov.in](http://www.cowin.gov.in) या  
आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करें।



जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और नदी नवनीकरण  
मंत्रालय  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,  
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION  
GOVERNMENT OF INDIA



## विषय वस्तु

- चमोली जिला, उत्तराखंड में ऋषिगंगा और धौलीगंगा में फ्लैश फ्लड
- बांध और नदी बेसिनों के संपोषणीय विकास हेतु आईसीओएलडी संगोष्ठी
- माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री का आगरा दौरा
- 7वीं आईडव्ल्यूडव्ल्यू - 2021 के लिए वैज्ञानिक समिति की दूसरी बैठक
- नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यदल की 13वीं बैठक
- "प्रतिगमन प्रभावित डौक बैराज, तीस्ता बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल की पुनःस्थापना" पर

### प्रस्तुति

- गंगा बेसिन में उत्तराखंड राज्य में ई-फ्लो मॉनिटरिंग के संबंध में सचिव (डीओडव्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) की बैठक
- जल जीवन मिशन- शहरी- बजट घोषणा
- तटीय सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति की 17वीं बैठक
- कीटनाशक विश्लेषण पर अर्ध दिवसीय कार्यशाला
- जल लेखापरीक्षा और जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का संशोधन
- बाढ़ संभावित क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन
- मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण और मुल्लापेरियार बांध पर 14वीं पर्यवेक्षी समिति की बैठक

- पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में जगनाथपुर सिंचाई योजना की डीपीआर
- केंद्रीय जल आयोग, गुवाहाटी को स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता पुरस्कार
- गनोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मेघालय-समीक्षा बैठक और सीडव्ल्यूसी डिजाइन टीम द्वारा साइट का दौरा
- प्रशिक्षण
- योजनाओं/संघटकों की वित्तीय प्रगति
- जल क्षेत्र समाचार
- जलाशय निगरानी
- इतिहास- घाटप्रभा नदी विकास
- गैलरी

## चमोली जिला, उत्तराखंड में ऋषिगंगा और धौलीगंगा पर फ्लैश फ्लड

उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गाँव में दिनांक 07.2.2021 को कथित भूस्खलन / जीएलओएफ के कारण बाढ़ आई। यह क्षेत्र ऋषिगंगा के किनारे है, जो धौलीगंगा की एक सहायक नदी है। धौलीगंगा अलकनंदा नदी की सहायक नदियों में एक है, जो उत्तराखंड के जोशीमठ पर्वत के आधार में विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है।

बाढ़ के अचानक प्रभाव के कारण, ऋषिगंगा नदी पर ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना और धौलीगंगा नदी पर तपोवन परियोजना को भारी क्षति पहुंची। इस अचानक आई बाढ़ में, कई लोगों/ कार्मिकों के लापता होने की सूचना और बाद में कुछ शव भी प्राप्त हुए।

जोशीमठ में अलकनंदा नदी पर धौलीगंगा नदी के संगम के अधोप्रवाह में स्थित बाढ़ निगरानी स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी और 16.06.2013 में देखे गए पूर्व एचएफएल 1385.54 मी. की तुलना में 07.02.2021 को 1388.65 तक का जल स्तर देखा गया। संगणित अधिकतम प्रवाह 1670 क्यूमेक था। जोशीमठ स्थल पर अलकनंदा नदी के बेड लेवल में औसत वृद्धि 3 मी. थी। अलकनंदा नदी पर पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर में केंद्रीय जल आयोग का बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन है। हालांकि, जोशीमठ के डाउनस्ट्रीम में बाढ़ सामान्य हो गई। जोशीमठ एचओ साइट से भूस्खलन के गुजरने के तुरंत बाद अलकनंदा नदी पर विभिन्न एचओ स्थलों पर हर घंटे जलस्तर की निगरानी की शुरूआत की गई।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने 07.02.2021 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की आयोजित बैठक में भाग लिया तथा समिति को सूचित किया कि डाउनस्ट्रीम स्थलों पर बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में जलस्तर सामान्य हो चुका है और भारी वर्षा की पूर्वानुमान नहीं होने से जोशीमठ से नीचे बाढ़ की संभावना नहीं है।

## बांध और नदी बेसिनों के संपोषणीय विकास हेतु आईसीओएलडी संगोष्ठी

द इंडियन नेशनल कमिटी ऑन लार्ज डैम्स (आईएनसीओएलडी), नई दिल्ली ने केंद्रीय जल आयोग तथा ड्रिप के सहयोग से आईसीओएलडी के तत्वाधान में बहुआयामी कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली में 24-27 फरवरी, 2021 के दौरान "बांध और नदी बेसिनों के संपोषणीय विकास पर संगोष्ठी का आयोजन किया। सीपीएमयू, ड्रिप ने 02 तकनीकी सत्रों नामतः "बांध सुरक्षा, जोखिम आकलन तथा प्रबंधन में प्रगति" "बांध संरचना कार्य में प्रगति" के संबंध में सहयोग दिया। सीपीएमयू, ड्रिप ने इस योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले इस कार्यक्रम के वर्चुअल प्रदर्शनी में भी भाग लिया। इस संगोष्ठी में माननीय जलशक्ति मंत्री, माननीय ऊर्जा एवं नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय जल आयोग के कार्मिक, आईसीओएलडी बांध के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

## माननीय राज्य मंत्री (जल शक्ति) का आगरा दौरा

श्री रतन लाल कटारिया, माननीय राज्य मंत्री(जल शक्ति), भारत सरकार ने 17.02.2021 को एनएमसीजी, सीडब्ल्यूसी, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्मिकों के साथ बैठक की तथा संबंधित कार्मिकों से विभिन्न कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय जल आयोग तथा विभिन्न संगठनों के अधिकारी/ कार्मिक भी इस बैठक में भाग लिए। श्री जी.एल. बंसल, निदेशक (एम एंड ए), आगरा और श्री मनोज कुमार, कार्यकारी अभियंता (एलवाईडी), के.ज.आ., आगरा ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के तहत किए जाने वाले कार्यों पर प्रस्तुति दी।



इसके बाद, देहरादून से केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने तपोवन और रैनी स्थलों का दौरा किया तथा दिनांक 15.02.2021 को जिला अधिकारी, चमोली, उत्तराखंड के साथ भेंट की। उन्होंने भूस्खलन के बाद अलकनंदा नदी पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए जा रहे हर घंटे बाढ़ निगरानी की सूचना दी।

लापता लोगों की खोज और बचाव कार्य की समीक्षा करने तथा उत्तराखंड के चमोली जिले में बने कृत्रिम झील के संबंध में आगामी कार्यनीति का निर्णय करने हेतु केंद्रीय गृह सचिव के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस वर्चुअल बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदा के कारणों का अध्ययन करने तथा भावी कार्ययोजना के विषय में सुझाव देने हेतु दो दलों का गठन किया। एक दल भूस्खलन बांध के अपस्ट्रीम क्षेत्र का अध्ययन करेगा तथा दूसरा दल इसके टूटने की स्थिति में डाउनस्ट्रीम प्रभाव के विषय में अध्ययन करेगा। निदेशक (एफएफएम) तथा निदेशक (हाइड्रोलोजी-दक्षिण), केंद्रीय जल आयोग दल-2 के सदस्य हैं, जो डाउनस्ट्रीम स्थलों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। इस टीम द्वारा 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। अध्ययन कार्य हेतु तथा आगामी कार्य योजना तैयार करने हेतु टीम लीडरों द्वारा वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।



इस कार्यक्रम के सत्रों को निम्नांकित लिंक से एक्सेस किया जा सकता है:-

[https://www.youtube.com/channel/UCIkCf\\_W6Y0ZhcZIP6LZSPoA/search?query=ICOLD](https://www.youtube.com/channel/UCIkCf_W6Y0ZhcZIP6LZSPoA/search?query=ICOLD)



## 7वीं आईडब्ल्यूडब्ल्यू -2021 के लिए वैज्ञानिक समिति की दूसरी बैठक

### 7th INDIA WATER WEEK 2021

THEME : WATER SECURITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH EQUITY

VENUE : INDIA EXPO CENTRE, GREATER NOIDA

16-20 NOVEMBER, 2021



7वें भारत जल सप्ताह - 2021 (आईडब्ल्यूडब्ल्यू- 2021) के लिए वैज्ञानिक समिति की दूसरी बैठक 22.02.2021 को के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में श्री एस. के. हालदार, अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में समिति के सदस्यों ने वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से भाग लिया। पहली बैठक के निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को नोट किया गया। पहली बैठक 23.09.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी।

दूसरी बैठक के दौरान, समिति ने विभिन्न उप-विषयों, संगोष्ठी और पैनल चर्चा के लिए विषयों, नोडल एजेंसियों, मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के विशेष आयोजनों पर विचार-विमर्श किया और अंतिम रूप दिया। समिति ने तकनीकी सत्रों के लिए पहचान की गई संभावित नोडल एजेंसियों से संपर्क करने का भी सुझाव दिया। आगे की योजना बनाई और पेपर जमा करने के लिए समय सीमा की रूपरेखा तैयार की।

समिति ने आईडब्ल्यूडब्ल्यू- 2021 के लिए प्रथम सूचना बुलेटिन और ड्राफ्ट इवेंट प्लानर के मसौदे की सामग्री पर विचार किया और

### नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यदल की 13वीं बैठक

जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार, श्री श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में 25.02.2021 को नई दिल्ली में नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स (टीएफ-आईएलआर) की तेरहवीं बैठक आयोजित की गई। प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक के एकीकरण की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई, अंत में दो चरणों में ईआरसीपी के घटकों की योजना बनाने का निर्णय लिया गया और एनडब्ल्यूडीए को चरण-1 की एफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया। केन-बेतवा लिंक के संबंध में, अध्यक्ष, टीएफ-आईएलआर ने एमओए पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने के लिए मुद्दों को सुलझाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा

### "प्रतिगमन प्रभावित डौक बैराज, तीस्ता बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल की पुनःस्थापना" पर प्रस्तुति

तीस्ता बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा "डौक बैराज के लिए किए जाने वाले पुनःस्थापना उपायों" के संबंध में एक विशेष समस्या को सिंचाई और जलमार्ग विभाग (आई एंड डब्ल्यूडी), पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2017 के दौरान केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया था। इस विशेष समस्या को मुख्य रूप से आई एंड डब्ल्यूडी, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तावित पुनःस्थापना उपायों के लिए किए गए डिजाइन पर विचार देने के लिए अनुरोध किया गया।

बैराज और नहर डिजाइन (पूर्व और उत्तर-पूर्व) निदेशालय, सीडब्ल्यूसी ने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित पुनःस्थापना उपायों के लिए

### गंगा बेसिन में उत्तराखंड राज्य में ई-फ्लो मॉनिटरिंग के संबंध में सचिव (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) की बैठक

सचिव (डीओडब्ल्यूआर, डी एंड जीआर) ने 25.02.2021 को ई-फ्लोसाइट के अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम पर रडार आधारित जल स्तर सेंसर और वेग सेंसर की स्थापना के संबंध में अध्यक्ष, के.ज.आ., डीजी, एनएमसीजी, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार और

वैज्ञानिक समिति की दूसरी बैठक के निर्णयों को शामिल करके उन्हें संशोधित करने का सुझाव दिया।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय), एनडब्ल्यूडीए ने आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2021 के साइड लाइन पर 16-17 नवंबर 2021 के दौरान ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स जल मंच से जुड़े दो दिवसीय ब्रिक्स कार्यक्रमों की योजना के लिए सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

समिति ने महसूस किया कि आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2021 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जल और सिंचाई मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है क्योंकि यह नीति निर्माताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच संवाद की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करेगा और इस आयोजन में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाएगा। समिति ने युवा पेशेवरों के लिए एक विशेष तकनीकी सत्र को डिजाइन और शामिल करने की भी सिफारिश की जिसे के.ज.आ. द्वारा समन्वित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ आयोजित कई बैठकों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया, जिस पर अंत में 22.03.2021 को हस्ताक्षर किए गए। गोदावरी के पानी को कावेरी बेसिन तक मोड़ने के वैकल्पिक प्रस्ताव के लिए, एनडब्ल्यूडीए को इस लिंक के स्रोत स्थान के रूप में इंचमपल्ली को सुनिश्चित करने और तदनुसार डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था। साथ ही मौजूदा ट्रिब्यूनल अवार्ड के आधार पर कावेरी और गोदावरी के पानी को साझा करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एमएसटीजी लिंक के मामले में विदेश मंत्रालय को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।



डिजाइन गणना की जांच करके अध्ययन किया। जांच के परिणाम परियोजना अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं।

के.ज.आ.के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड में के.ज.आ.द्वारा पहचाने गए स्थानों के अनुसार स्वचालित डेटा अधिग्रहण और ट्रांसमिशन उपकरण की स्थापना के लिए सभी परियोजना प्राधिकरणों से संपर्क करने का निर्णय लिया गया।

## जल जीवन मिशन- शहरी- बजट घोषणा

अपने बजट भाषण के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की, जिसे एसडीजी लक्ष्य- 6 के अनुसार सभी 4,378 सांविधिक शहरों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### मिशन की मुख्य विशेषताएं

- जेजेएम(यू) के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय ₹2,87,000 करोड़ है जिसमें अमृत मिशन को जारी वित्तीय सहायता के लिए ₹10,000 करोड़ शामिल हैं।
- जेजेएम (यू) के तहत 2.68 करोड़ शहरी घरेलू नल कनेक्शनों को कवर करने का प्रस्ताव है। इसी तरह 500 अमृत शहरों में जेजेएम (यू) में कवर किए जाने के लिए 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन/सेप्टेज प्रस्तावित है।
- स्थायी ताजे पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल निकायों का कार्याकल्प और शहरी जलभृत प्रबंधन योजना के माध्यम से बाढ़ को कम करने और सुविधा बढ़ाने के लिए हरित स्थान और स्पंज शहर बनाना मिशन के अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं।
- जेजेएम (यू) उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों के कार्याकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। संस्थागत तंत्र के विकास के साथ पानी की 20 फीसदी मांग को पुनः उपयोग किए गए पानी से पूरा किया जाना है।
- पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल की

## तटीय सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति की 17वीं बैठक

तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीपीडीएसी) सभी समुद्री राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी तटीय कटाव की समस्याओं पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। सीपीडीएसी की 17वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 18.02.2021 को श्री रंजन कुमार सिन्हा, सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समुद्री राज्यों और

## कीटनाशक विश्लेषण पर अर्ध दिवसीय कार्यशाला

वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 19.02.2021 को सीएंडएसआरओ, के.ज.आ., कोयंबटूर द्वारा पानी के नमूने के कीटनाशक विश्लेषण पर एक अर्धदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन सदस्य (आरएम), के.ज.आ., नई दिल्ली द्वारा किया गया। प्रारंभ में, अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने भारत में नदियों की जल गुणवत्ता निगरानी के महत्व की ओर इशारा किया और महामारी/लॉक-डाउन अवधि के दौरान वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा। इसके अलावा, उन्होंने कामना व्यक्त की कि इस कार्यशाला से साझा की गई चर्चा और जानकारी के.ज.आ.के सभी वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी।

तत्पश्चात, मुख्य अभियंता, सीएंडएसआरओ, के.ज.आ., कोयंबटूर और मुख्य अभियंता, पीएंडडीओ, के.ज.आ., नई दिल्ली ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। मुख्य अभियंता (पीएंडडी), के.ज.आ. ने कृषि में कीटनाशकों के अनुचित उपयोग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नदी के पानी की गुणवत्ता के प्रभाव और नदी के पानी में कीटनाशक की निगरानी की आवश्यकता के मूल्यांकन की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला।

पानी के नमूने में कीटनाशकों के निष्कर्षण और विश्लेषण के महत्व पर अपनी प्रस्तुति में, श्रीमती एल प्रियधरसिनी, एआरओ,

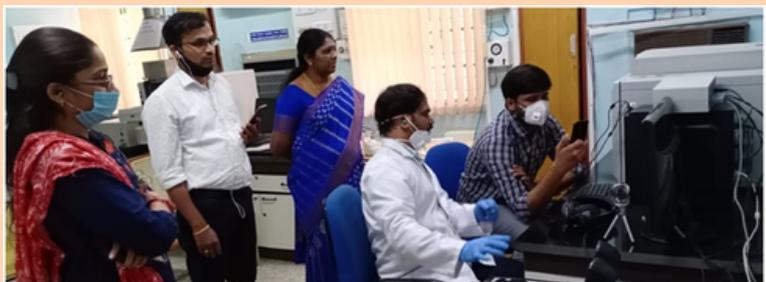
मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों के मानचित्रण के लिए एक चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से शहरों में पेय जल सर्वेक्षण किया जाएगा।

- शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने और शहरों की जल सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ मिशन का एक सुधार एजेंडा है। प्रमुख सुधार गैर-राजस्व पानी में 20% की कमी; शहर की कुल पानी की मांग का कम से कम 20% और राज्य स्तर पर औद्योगिक पानी की मांग के 40% को पूरा करने के लिए उपचारित उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण; दोहरी पाइपिंग प्रणाली,
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने कुल परियोजना निधि आवंटन के न्यूनतम 10 प्रतिशत की पीपीपी परियोजनाओं को अपनाएं।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 100% केंद्रीय वित्त पोषण होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए, परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्त पोषण 90% होगा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए केंद्रीय वित्त पोषण 50%, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों के लिए एक तिहाई और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 25% होगा।
- परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से वित्त पोषण 20:40:40 के तीन चरणों में होगा। प्राप्त परिणामों के आधार पर तीसरी किस्त जारी की जाएगी और वित्त पोषण के दौरान विश्वसनीय बहिष्करण का प्रयोग किया जाएगा।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1694420>



केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार/संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया।



एलसीडब्ल्यूक्यूएल, के.ज.आ., कोयंबटूर ने गैस क्रोमेटोग्राफ (जीसी) का उपयोग करके पानी के नमूनों में कीटनाशक के विश्लेषण में प्राप्त विभिन्न पहलुओं और ज्ञान को साझा किया। कार्यशाला के दौरान, जीसी का उपयोग करते हुए नमूना विश्लेषण का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सिद्धांतों तथा व्यावहारिक प्रदर्शन सत्रों के साथ गैस क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोगों पर एक त्वरित नज़र डालना था जो प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर सके।

अपनी समापन टिप्पणी में, निदेशक, आरडीसी-II, के.ज.आ., नई दिल्ली ने प्रासंगिक क्षेत्र में सीखने की क्षमता में सुधार के लिए वैज्ञानिक समुदाय के बीच ज्ञान-साझाकरण के महत्व को इंगित किया और प्रतिभागियों को भविष्य में पानी की गुणवत्ता के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति से सम्बन्धित इसी प्रकार अन्य तकनीकी कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया।

## ड्रिप

### मुख्य सचिव, गुजरात सरकार और एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूएस और केडी, गुजरात के अधिकारियों की ड्रिप (डीआरआईपी) चरण - II के संबंध में 05 फरवरी, 2021 को गांधीनगर में बैठक

श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, डीओडब्ल्यूआर आरडी एंड जीआर ने श्री अनिल मुकीम, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के साथ 05.02.2021 को भेंट की। जिसके बाद, नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग (एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूएस और केडी), गुजरात के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। अपर सचिव ने मुख्य सचिव को चल रही बाह्य सहायता प्राप्त योजना डीआरआईपी के साथ-साथ नई शुरू की गई योजना डीआरआईपी चरण II और चरण III से अवगत कराया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय ने की, जिसमें डीआरआईपी चरण- II से संबंधित आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के तैयारी मानदंड के संबंध में एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूएस और केडी की स्थिति पर विचार-



विमर्श किया गया था। एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूएस और केडी की टीम का नेतृत्व श्री एम. के. जादव, सचिव, एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूएस एंड केडी, गुजरात सरकार ने किया।

### यूजेवीएनएल, टैंजेडको और तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी के बांधों के लिए प्रकाशित ईएपी के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 08 फरवरी, 10 फरवरी और 25 फरवरी, 2021 को हितधारक परामर्श बैठकें

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के 2 बांधों, टीएनएनजीईडीसीओके 7 बांधों और तमिलनाडु डब्ल्यूआरडीके 11 बांधों के लिए प्रकाशित आपातकालीन कार्य योजनाओं (ईएपी) का प्रचार-प्रसार करने के लिए हितधारक परामर्श बैठकें, कार्यान्वयन आवश्यकता के एक भाग के रूप में, वर्चुअल रूप में क्रमशः 8, 10 और 25 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई।



### जल लेखापरीक्षा और जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का संशोधन

दिनांक 16.02.2021 को वर्चुअल प्रणाली के माध्यम से 'जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देश' के संशोधन के लिए समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता, पीओएमआईओ, के.ज.आ. ने की और इसमें समिति के सदस्यों और विभिन्न संगठनों के नामित अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के बीच दिशानिर्देशों को संशोधित करने पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई और सभी ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देश पहली बार 2005 में के.ज.आ. द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसका उद्देश्य जल उपयोग के सभी क्षेत्रों में जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण को शुरू करना, मानकीकृत करना और लोकप्रिय बनाना था।

### बाढ़ संभावित क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन

भारत में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए, मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अधीन एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है जिसमें जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष और के.ज.आ.के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/निदेशक सदस्य-सचिव हैं। क्षेत्रीय समितियों का अधिदेश विशेषज्ञ समिति द्वारा निश्चित की गई कार्यप्रणाली, वर्गीकरण और मानदंड के आधार पर अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान, सीमांकन और वर्गीकरण करना है। सितंबर, 2020 में हुई विशेषज्ञ समिति की छठी बैठक में के.ज.आ.द्वारा किए गए अध्ययन और प्रयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पर सहमति हुई। तत्पश्चात यह भी सहमति हुई कि असम, बिहार और ओडिशा राज्यों के संबंध में अध्ययन चालू वर्ष के



चूंकि दिशानिर्देशों के प्रकाशन के बाद से प्रौद्योगिकियों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, इसलिए नवीनतम उपकरणों और अवधारणाओं को शामिल करने के लिए दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करना वांछनीय है।

बाढ़ डेटा / उपग्रह इमेजरी सहित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि शेष राज्यों के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नक्शे क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से संबंधित राज्यों को जमीनी सत्यापन के लिए भेजे जाएंगे।

उक्त संदर्भ में दिनांक 10.02.2021 को मुख्य अभियंता (पीएंडडी), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ एक बैठक आयोजित की गई और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन पर प्रारूप रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। अगली बैठक अध्ययन पर अपने बहुमूल्य निश्चित और टिप्पणियां प्रदान करने और जमीनी सत्यापन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए गठित क्षेत्रीय समिति के सभी सदस्यों के साथ निर्धारित की जानी है। के.ज.आ., देहरादून ने उत्तराखंड राज्य में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए उत्तराखंड सरकार से भी संपर्क किया है।

## मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण और मुल्लापेरियार बांध पर 14वीं पर्यवेक्षी समिति की बैठक

मुल्लापेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति की 14वीं बैठक दिनांक 19.02.2021 को कुमिली, केरल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य बांध, मिट्टी के तटबंध, बेबी डैम और इसकी संलग्न संरचनाओं जैसे दीर्घाओं, हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों आदि से जुड़े बांध का निरीक्षण श्री गुलशन राज, अध्यक्ष (मुल्लापेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति) और मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ., श्री प्रणबज्योति नाथ (सचिव, डब्ल्यूआरडी, केरल), श्री आर सुब्रमण्यम (अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू, डब्ल्यूआरडी तमिलनाडु) और केंद्रीय जल आयोग व केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। समिति के दृश्य निरीक्षण में बांध और उससे जुड़ी संरचनाओं की समग्र स्थिति संतोषजनक पाई गई।

बैठक के दौरान, पर्यवेक्षी समिति के दायरे में विभिन्न एजेंडा मदों पर चर्चा की गई। समिति ने कावेरी तकनीकी सेल, डब्ल्यूआरडी, तमिलनाडु के परामर्श से केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार मुल्लापेरियार बांध के लिए रूल कर्व पर विचार-विमर्श किया। इनफ्लो पूर्वानुमान प्रणाली के कार्यान्वयन की वर्तमान प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया और भविष्य की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। सीस्मोमीटर और एक्सेलेरोमीटर की खरीद और स्थापना की स्थिति से समिति को



अवगत कराया गया। बांध स्थल पर सड़क सुधार कार्य में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई और इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना पर विचार किया गया। बेबी डैम की सुरक्षा और बेबी डैम को मजबूत करने के लिए पेड़ों को हटाने के संबंध में अनुमति की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। संचालन और रखरखाव (ओएंडएम मैनुअल) के अद्यतन और आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) की तैयारी पर भी चर्चा हुई।

## पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में जगन्नाथपुर सिंचाई योजना की डीपीआर

दिनांक 29.08.2017 को के.ज.आ. और जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के बीच 31 सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण और जांच हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इन 31 परियोजनाओं में से, 20 परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन संगठन (बी एंड बीबीओ), के.ज.आ., शिलांग को सौंपा गया, जबकि 11 परियोजनाओं को यमुना बेसिन संगठन (वाईबीओ), के.ज.आ., नई दिल्ली के तहत योजना परिमंडल, के.ज.आ., फरीदाबाद को सौंपा गया। उक्त कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत का 10% दिसंबर, 2017 में जारी कर दिया गया। सभी योजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार को जून 2018 में प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावित जगन्नाथपुर सिंचाई योजना का बांध स्थल देव नदी/नाला पर स्थित है जोकि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर ब्लॉक में करो नदी की सहायक नदी है। इस योजना के माध्यम से, 640 हेक्टेयर सीसीए को 200% की सिंचाई तीव्रता पर सुनिश्चित सिंचाई प्रदान की जा सकती है। खरीफ और रबी मौसम में कमान क्षेत्र में 100% सिंचाई (640 हेक्टेयर) होगी। पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के मोंगरा, केंदुपोसी, कोचरा, छोटा पोसी बल्याडीह, महोतोसाई, कुंडियासाई और हेसोपी कमान क्षेत्र के गांव लाभान्वित होंगे। पीने के लिए 2.277 एमसीएम और औद्योगिक उपयोग के लिए 0.600 एमसीएम जल के अलावा सिंचाई के लिए



पानी का कुल वार्षिक उपयोग 6.621 एमसीएम है।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 70.61 करोड़ रु. है। परियोजना की शुद्ध वार्षिक लागत रु. 7.31 करोड़ है। योजना से प्राप्त होने वाला वार्षिक लाभ रु. 9.91 करोड़ है। जगन्नाथपुर सिंचाई योजना का बीसी अनुपात 1.36 है और इसलिए यह योजना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

जगन्नाथपुर सिंचाई योजना के डीपीआर के सभी अध्यायों को योजना और अन्वेषण मण्डल, के.ज.आ., फरीदाबाद के तहत योजना और अन्वेषण उप-मंडल, जमशेदपुर के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण, क्षेत्र की जांच और जल-मौसम संबंधी प्रेक्षणों के बाद अंतिम रूप दिया गया है। डीपीआर अंततः दिनांक 15.2.2021 को डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार को सौंप दिया गया।

## केंद्रीय जल आयोग, गुवाहाटी को स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता पुरस्कार

गुवाहाटी नगर निगम ने विभिन्न स्कूलों, अस्पतालों, होटलों, सरकारी कार्यालयों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले बाजारों के बीच 'स्वच्छता' प्रतियोगिता आयोजित की थी, जो परिसर की सफाई, शौचालय की उपलब्धता और सफाई, श्रमिकों की स्वच्छता, कूड़ेदान की उपलब्धता (नीला और हरा), बुनियादी ढांचे का रखरखाव और सफाई आदि जैसे विभिन्न मानदंडों को पूरा करने पर आधारित थी। सरकारी कार्यालयों में केंद्रीय जल आयोग को तीसरा पुरस्कार मिला।



## गनोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मेघालय-समीक्षा बैठक और के.ज.आ. डिजाइन टीम द्वारा साइट का दौरा

गनोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित 22.50 (3 x 7.50) मेगावाट की परियोजना है। के.ज.आ. टीम द्वारा एक समीक्षा बैठक और स्थल का दौरा किया गया। हाइड्रल-सिविल डिजाइन (एचसीडी) की और कंक्रीट और चिनाई बांध डिजाइन (सीएमडीडी) और तटबंध विभाग की टीम ने स्थलका अलग अलग दौरा किया। एचसीडी (ईएंडएनई) निदेशालय से, श्री अभिनव श्रीवास्तव, उप निदेशक ने श्री वैसाख, उप निदेशक और श्री सजल मित्तल, सहायक निदेशक के साथ टीम का नेतृत्व किया। बांध निदेशालय की अन्य टीम का नेतृत्व श्री ए. राघवेंद्रे, उप निदेशक ने श्री के.एस. सैनी, सहायक निदेशक और श्री मधुकांत गोयल, सहायक निदेशक के साथ किया। बैठक और स्थल के दौरे के दौरान एमईपीजीसीएल (मेघालय सरकार), मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग



लिमिटेड और मैसर्स टीपीएससी के अधिकारी भी उपस्थित थे।

### प्रशिक्षण

#### (क) एनडब्ल्यूए द्वारा संचालित कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	दिनांक एवं अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	श्रेणी
(क)	सीडब्ल्यूसी के कनिष्ठ अभियंताओं के लिए अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच 3)	01-26 फरवरी 2021	38	संवर्ग प्रशिक्षण
(ख)	राजस्थान राज्य के लिए पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के लिए "जल संरक्षण और प्रबंधन" पर प्रशिक्षण-सह-वेबिनार	09-11 फरवरी 2021	172	जन जागरूकता कार्यक्रम
(ग)	बाढ़ संरक्षण, कटाव रोधी और नदी प्रशिक्षण कार्य	15-17 फरवरी 2021	108	उद्देश्य उन्मुख
(घ)	गूगल अर्थ इंजन और उसका अनुप्रयोग जल	15-19 फरवरी 2021	137 (पंजीकृत)	उद्देश्य उन्मुख

#### (ख) वेबिनार श्रृंखला

क्रमांक.	दिनांक	वेबिनार का विषय	प्रतिभागियों की संख्या	यूट्यूब लिंक
1.	25.01.21	जल के बंटवारे के लिए करार	73	<a href="https://youtu.be/L2vtVAF-3Qo">https://youtu.be/L2vtVAF-3Qo</a>
2.	01.02.21	अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और जल शासन - मुद्दे और चुनौतियाँ	91	<a href="https://youtu.be/6kTBDxqfpnk">https://youtu.be/6kTBDxqfpnk</a>
3.	05.02.21	जल गुणवत्ता विश्लेषण में नवीनतम तकनीकों पर वेबिनार	79	
4.	08.02.21	नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ने में अंतर्राज्यीय मुद्दों की चुनौतियाँ	111	<a href="https://youtu.be/8iDv54gCRGY">https://youtu.be/8iDv54gCRGY</a>

### 28.02.202 तक योजनाओं/संघटकों की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

क्रम संख्या	योजना/संघटक का नाम	संशोधित अनुमान (2020-21)	व्यय	व्यय (% में)
1.	जल संसाधन सूचना तंत्र का विकास	130.00	111.182	85.5%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं का अन्वेषण	9.000	7.849	87.2%
3.	बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	10.576	8.749	82.7%
4.	अवसंरचना विकास योजना	5.750	5.553	96.6%
5.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	8.886	7.245	81.52%
6.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना	21.000	16.200	77.14%

## डेटा कॉर्नर- बेसिन वार सतही जल निगरानी

क्रम संख्या	बेसिन	कुल स्टेशन	मैनुअल स्टेशनों की संख्या	टेलीमेट्री स्टेशनों की संख्या
1	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी का क्षेत्र	20	18	2
2	बराक और अन्य	90	81	9
3	ब्रह्मपुत्र	261	224	37
4	ब्राह्मणी और बैतरणी	33	19	14
5	कावेरी	72	72	0
6	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	131	91	40
7	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	72	71	1
8	गंगा	1,466	1,341	125
9	गोदावरी	500	481	19
10	सिंधु (सीमा तक)	156	102	54
11	कृष्णा	207	183	24
12	महानदी	103	101	2
13	माही	123	109	14
14	म्यांमार और बांग्लादेश में बहने वाली छोटी नदियाँ	32	32	0
15	नर्मदा	95	91	4
16	पेन्नार	35	26	9
17	साबरमती	115	104	11
18	सुवर्णरेखा	30	19	11
19	तापी	104	88	16
20	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	72	72	0
21	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	133	126	7
22	लूणी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	351	336	15
23	कुल	4,199	3,785	414

स्रोत: इंडिया वारिस , फरवरी 2021 तक

## जल क्षेत्र समाचार

- पास से ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी : पीएम मोदी (राजस्थान पत्रिका, 01.03.2021)
- सरकार तैयार कर रही वर्षा जल संचयन का ब्लूप्रिंट (राष्ट्रीय सहारा, 03.03.2021)
- जलवायु परिवर्तन पर भारत—स्वीडन मिलकर कर सकते हैं काम : मोदी (राष्ट्रीय सहारा, 06.03.2021)
- ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने में तेजी ला रहा चीन, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर असर (हरिभूमि, 09.03.2021)
- पुराने पड़ते बांधों के जोखिम (जनसत्ता, 10.03.2021)
- देश के सभी 4378 शहरों में 2.86 करोड़ घर पानी कनेक्शन से जुड़ेंगे (दैनिक भास्कर, 12.03.2021)
- जीवनदायिनी यमुना पर पहला बांध — ड्रीम प्रोजेक्ट से बुझेगी हरियाणा के तीन करोड़ लोगों की प्यास (अमर उजाला, 13.03.2021)

- बिहार में 17वीं सदी में शुरू हुई नदियों को जोड़ने की योजना देशभर में जल्द लागू होगी : शेखावत (दैनिक भास्कर, 14.03.2021)
- केन—बेतवा विवाद : उग्र को 750 एमसीएम पानी देने पर सहमति (दैनिक जागरण, 15.03.2021)
- नदी जल बंटवारे पर भारत—बांग्लादेश की बैठक आज (राष्ट्रीय सहारा, 16.03.2021)
- नदियों के जल प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और बांग्लादेश (जनसत्ता, 18.03.2021)
- विश्व जल दिवस विशेष — दुनिया में 78 करोड़ से ज्यादा लोग शुद्ध जल से वंचित (राजस्थान पत्रिका, 21.03.2021)
- सिंधु जल बंटवारे पर भारत—पाक के बीच आज से वार्ता (दैनिक जागरण, 23.03.2021)
- देश की 58 हजार ग्रामीण बस्तियों का भूजल दूषित (राष्ट्रीय सहारा, 29.03.2021)

## जलाशय निगरानी

के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) में फरवरी 2021 के महीने में नीचे दिये गए दो और जलाशयों को जोड़ा गया है।

जलाशय का नाम	राज्य	सक्रिय भंडारण क्षमता (बीसीएम)
मंदिरा बांध	ओडिशा	0.309
कंडालेरु	आंध्र प्रदेश	1.792
<b>कुल</b>		<b>2.101</b>

अब, के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 130 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ प्रदान होता है। इन 130 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 174.233 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 67.58% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 25.02.2021 के अनुसार, इन

### इतिहास- घाटप्रभा नदी विकास योजना

घाटप्रभा नदी अपनी दो मुख्य सहायक नदियों हिरण्यकेशी और ताम्रपर्णी के साथ, महाराष्ट्र-कर्नाटक क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके पास पर्याप्त जल संसाधन हैं। नदी पश्चिमी घाट नई अंबोली की सह्याद्री श्रेणी से निकलती है और आम तौर पर पूर्वी दिशा में बहती है और बीजापुर जिले में कृष्णा नदी में मिलती है। घाटप्रभा नदी में मानसून के मौसम में 127 से 381 सेंटीमीटर की सुनिश्चित वर्षा के साथ घाट से जल प्राप्त करने वाला एक अच्छा जलग्रहण क्षेत्र है और जिसमें सालाना अनुमानित औसत 0.03 लाख एमसीएम जल बहता है।

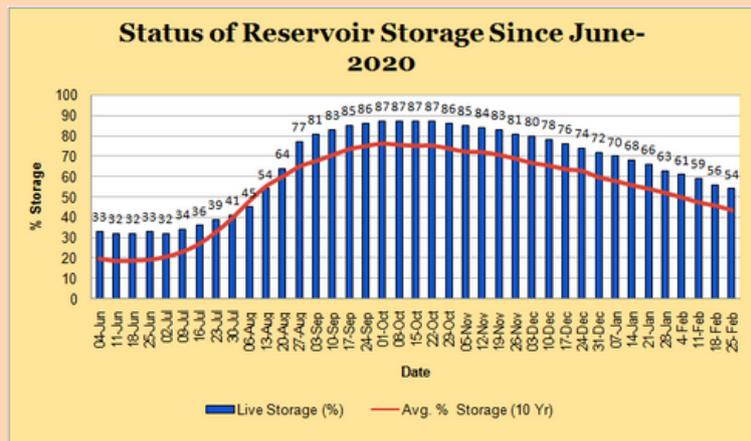
#### प्रारंभिक विकास

घाटप्रभा घाटी विकास योजना की संकल्पना 1852 से है जिसमें गोकक फाल की प्राकृतिक ऊंचाई का उपयोग करके सिंचाई के लिए नदी के पानी के संरक्षण का उद्देश्य था। प्रारंभिक सर्वेक्षण 1853 में किए गए थे और फॉल्स से लगभग 3.2 किमी ऊपर एक नहर के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे। गोकक फाल से 4 किमी ऊपर धुपदल के पास नदी पर एक चिनाई वाले बांध के निर्माण की एक योजना और एक नहर जिसे गोकक नहर कहा जाता है, को सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य के रूप में मंजूरी दी गई थी। यह योजना 1897 में 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरी हुई थी। आगे के विकास के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया गया, लेकिन सभी को खराब रिटर्न के आधार पर स्थगित कर दिया गया।

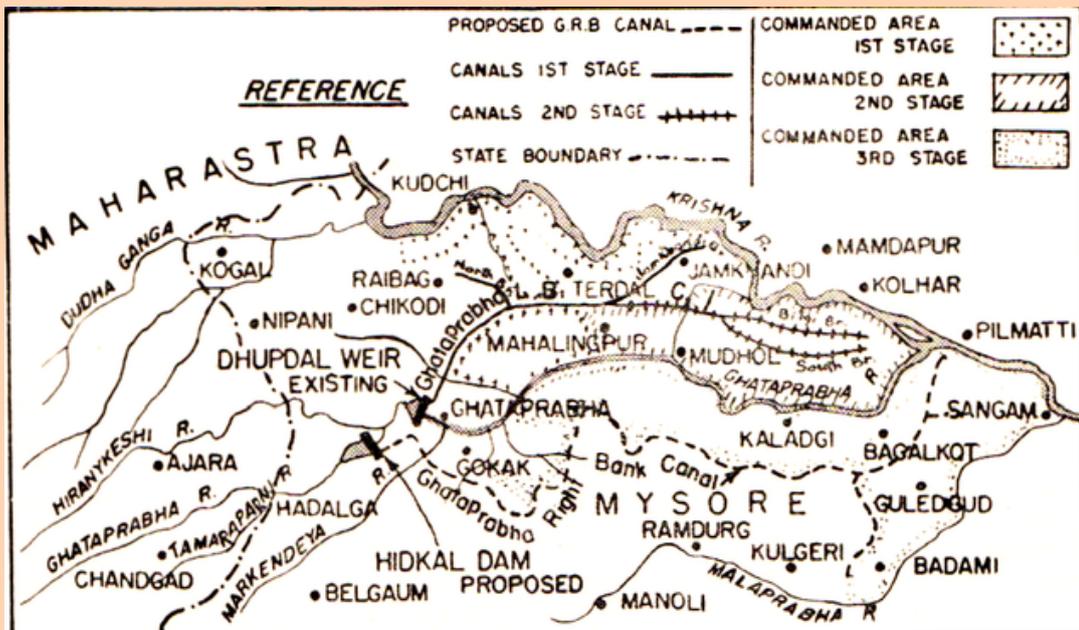
#### परियोजना की विशेषताएं

योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावों को तीन चरणों में अंतिम रूप दिया गया:

(i) 50 किमी शाखा नहरों को मिलाकर मौजूदा धुपदल वियर के बाएं किनारे पर 70.4 किमी लंबी नहर का निर्माण



जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 93.536 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 53.684% है। हालांकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 104.288 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत सक्रिय भंडारण 75.755 बीसीएम है। इस प्रकार, बुलेटिन दिनांक 25.02.2021 के अनुसार 130 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का लगभग 90% और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का लगभग 123% है।



- (ii) (क) घाटप्रभा बाएं किनारे की नहर का विस्तार 114 किमी के साथ-साथ कुल 96 किमी लंबाई की तीन शाखाओं के साथ और (ख), मौजूदा धुपदल वियर से लगभग 19.2 किमी अपस्ट्रीम में हिडकल पर एक स्टोरेज बांध का निर्माण;
- (iii) (क) हिडकल से स्टोरेज बांध से लेकर 192 किमी लंबी घाटप्रभा राइट बैंक नहर का निर्माण, (ख) हिडकल में स्टोरेज बांध की ऊंचाई बढ़ाना।

#### प्रथम चरण

पहले चरण के तहत काम मूल रूप से पूर्व बॉम्बे सरकार द्वारा ग्रो मोर फूड अभियान के तहत शुरू किया गया था और बाद में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया था।

नहर प्रस्तावित हिडकल बांध के लगभग 19.2 किमी डाउन-स्ट्रीम स्थित मौजूदा धुपदल वियर से निकलती है। घाटप्रभा लेफ्ट बैंक कैनाल और उसकी उत्तरी और जामखंडी शाखाओं के 70.4 किमी निर्माण की लागत 545 लाख रुपए थी। पुरानी गोकक नहर के तहत

7554 हेक्टेयर सहित इस प्रणाली की कुल कमान 104368 हेक्टेयर थी। अनुमानित सिंचित क्षेत्र 48,562 हेक्टेयर था। नहर की अधिकतम वहन क्षमता 57 क्यूमेक थी जिसकी चौड़ाई 9 से 21 मीटर के बीच थी।

### द्वितीय चरण

(क) घाटप्रभा बाईं नहर का विस्तार अक्टूबर 1956 में 70.4 से 113.6 किलोमीटर तक 468 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर किया गया था। नहर के इस हिस्से के अंतर्गत सकल कमान क्षेत्र 76,040 हेक्टेयर था। विस्तार की शुरुआत में डिस्चार्ज 23.5 क्यूमेक था। संपूर्ण नहर की कुल सकल कमान 180,410 हेक्टेयर थी। इस सकल कमान 120,600 हेक्टेयर में से बेलगाम और बीजापुर जिलों में क्षेत्रों को सिंचित करने का प्रस्ताव था।

### (ख) हिडकल बांध

हिडकल बांध का पहला चरण फरवरी 1960 में स्वीकृत किया गया था। बांध को बेलगाम जिले के हुकेरी तालुका में हिडकल गांव के पास घाटप्रभा नदी पर बनाने का प्रस्ताव था। बांध में 616 एमसीएम जल की प्रभावी क्षमता के साथ 660 एमसीएम जल संग्रहण था, जो घाटप्रभा बायीं नहर के माध्यम से 1.2 लाख हेक्टेयर के लिए पर्याप्त था। बांध पर, नदी के घाटी के जलग्रहण क्षेत्र के 1,410 वर्ग किमी से जल एकत्र होता है। जलाशय का अधिकतम जल फैलाव 47 वर्ग किमी था। इसने 20 गांवों में 15000 लोगों के 5760 हेक्टेयर भूमि को जलाप्लावित कर दिया।

शीर्ष पर 4,237 मीटर लंबे चिनाई वाले बांध के बाएं किनारे पर निचले

### गैलरी

घाटप्रभा घाटी विकास योजना विशेषताएँ एक दृष्टि में	
स्थल:	कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिले के हुकेरी तालुका में हिडकल गांव के पास घाटप्रभा नदी पर
बांध:	
प्रकार	चिनाई
ऊंचाई	51 मी (नदी तल के ऊपर सर्वाधिक)
लंबाई	4237 मी
डाइक:	
लंबाई	4354 मीटर
जलाशय	
भंडारण क्षमता (प्रथम चरण)	660 मिलियन घन मी.
कैचमेंट क्षेत्र	1410 वर्गकिमी
नहरें:	
बायीं नहर	114 किमी
ब्रांच	146 किमी
दायीं नहर	192 किमी
लाभ:	
सिंचाई	2.41 लाख हे.
लागत	36.13 करोड़ रु.

गैप को बंद करने के लिए 3962 मीटर और 392 मीटर लंबाई के दो डाइक थे। स्पिलवे को 4,615 क्यूमेक की बाढ़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। नदी के तल से बांध की अधिकतम ऊंचाई 51 मीटर थी। बांध के पहले चरण की लागत 850 लाख रुपए थी।

घाटप्रभा घाटी विकास योजना के तीसरे चरण में 550 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ 784 एमसीएम अतिरिक्त जल भंडारण के लिए हिडकल बांध की ऊंचाई बढ़ाना था जिससे घाटप्रभा दायीं नहर को आपूर्ति की जा सके।

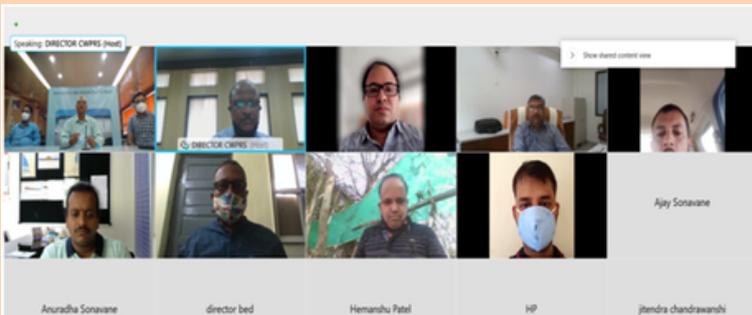
स्रोत: भगीरथ



श्री जितेंद्र पंवार, निदेशक(मॉनिटरिंग) ने 03-05 फरवरी, 2021 के दौरान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत यतिनहोल फेज II परियोजना का दौरा किया- यतिनहोल ग्रेविटी मेन कैनाल तहत निर्माणाधीन प्रमुख एक्वाडक्ट



केन-बेतवा लिंक परियोजना के आरडी 10.00 किमी पर प्रस्तावित साइफन डक्ट का साइट दौरा (धसान नदी का बायीं किनारा)



उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली गतिविधियों पर तटीय डेटा संग्रह की भूमिका, विधि और महत्व पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण 24.02.2021 को आयोजित किया गया



प्रीस्ट्रेस्ड टूनिंग गार्डर,पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश



### केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध  
कार्यालय

### संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य

- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी)- सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

### अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केंद्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
ई-मेल: media-cwc@gov.in